VOICE

A Tribute to the Golden Jubilee Year of
Mata Sundri College for Women (1967-2016)

Principal's Message

I take this opportunity to congratulate the Department of Political Science for putting together the debut edition of their E-Journal 'VOICE'. This initiative is an excellent platform as it encourages budding talents by bringing to the fore the creativity of young minds which have no boundaries and are filled with zest for life. The E-Journal is a fascinating read by way of its eclectic amalgamation of contents.

I wish the Department all the very best in all their forthcoming issues.

Dr. Kawarjit Kaur
Principal

FROM THE EDITOR'S DESK

2016 is a historic year in the true sense of the word. Indian Democracy is well into its 70th year, which is no mean achievement. Coincidentally, it is also the golden jubilee year of our esteemed institution and as a tribute to this beloved institution, the Department of Political Science has put forth its first ever E-Journal titled 'VOICE'.

Knowledge is infinite and so are the ways to acquire it. The tools of acquiring knowledge before a student are many, learning and expressing is just the beginning of a life-long process. It cannot be denied that the life of a student inside the classroom, amidst set curriculum and institutional training finds an important parallel in that outside it, and this is what motivates the students to explore unconventional terrain and to develop new ways of thinking.

Named aptly so, the journal 'VOICE' is an avenue to connect flowing thoughts by way of putting together the aspirations and artistic expressions of the students. Since this is a debut edition, the enthusiasm in putting it together has been without a parallel. However, this is only a humble attempt aimed at providing not only an intellectual but a comprehensive and holistic platform for the students to voice their views pertaining to larger issues of society, environment, policies and the world at large.

'VOICE' is also an attempt to commemorate seventy years of Indian democracy. The democratic journey which began with Nehru's famous speech 'Tryst with Destiny' has progressed through various phases – representing both blissful and challenging moments, which is beautifully reflected through the myriad contents of our e-journal.

Expressed by ways of essays, poems, articles, political cartoons, satire, and interviews we have tried to voice our creativity and freedom of expression– about various facets of society, as well as to question set patterns and in the bargain contribute towards building a new society.

The student editors have put in their all. Their exuberance, hard work and zeal have been phenomenal. Our hearts are filled with pride for having worked with such a creative team. During the selection of the contents of the e-journal 'VOICE', we have been mindful of certain factors significant to the entire process such as respect and concern for the institution's long cherished values and goals.

Needless to add, we reserve our sincere gratitude for the Principal Dr. Kawarjit Kaur for her constant encouragement and unrelenting support.

Faculty Editors

Dr. Madhuri Sukhija

Ms. Paromita Datta

Ms. Shashwati

Students Speak

What better way to commemorate the golden jubilee of our college than bringing forth a novel concept that will add to the legacy of this great institution. So here we present 'Voice', the e-journal from the department of political science.

'Voice' seeks to provide a platform for the students to showcase their manifold talents in the sphere of writing as well as in other avenues of creative expression. It opens up before the students a vibrant scope to cultivate and express their thoughts, uninhibited by the rigors of set curricula. The journal aims to push the students to stretch the contours of theoretical knowledge acquired in the classrooms to understand the reality around them, no less to prepare for them.

The e-journal encompasses a plethora of articles, poems, drawings, interviews, photographs and the list goes on. A section towards the end of the journal, called Reminiscences, provides through snapshots, glimpses of the activities, performances and achievements of our department in the semester that is fast slipping by.

The past few months have indeed been an exciting journey for the editorial team and at the same time filled with a lot of hardwork and a few challenges that came by in putting together the very first issue of our e-journal 'VOICE'.

We would like to thank the Head-of-Department, Political Science and faculty editor Dr. Madhuri Sukhija for igniting the spark in us and for taking the initiative of starting this e-journal. Her refreshing ideas and valuable inputs have gone a long way in the preparation of this journal.

In equal measure, we are also thankful to our other faculty editors. Ms. Shashwati, Ms. Paromita Dutta. Their able guidance at every step and unstinting support towards this initiative has been truly amazing.

We are glad to share that in keeping with our responsibility towards green environment and to ensure comfortable access we opted for an electronic format for the journal.

We take this opportunity to invite students of the department and college at large to contribute actively in keep the 'Voice' audible in the coming years.

We look forward to your blessings and good wishes.

Student Editors

Drishti Banerjee-President

Shaheen-Vice President

Rupal-Secretary

CONTENTS
Essays
Masterstrokes
Poetry
Interviewing The Young Democrats
The Semester Gone By
Reminiscences

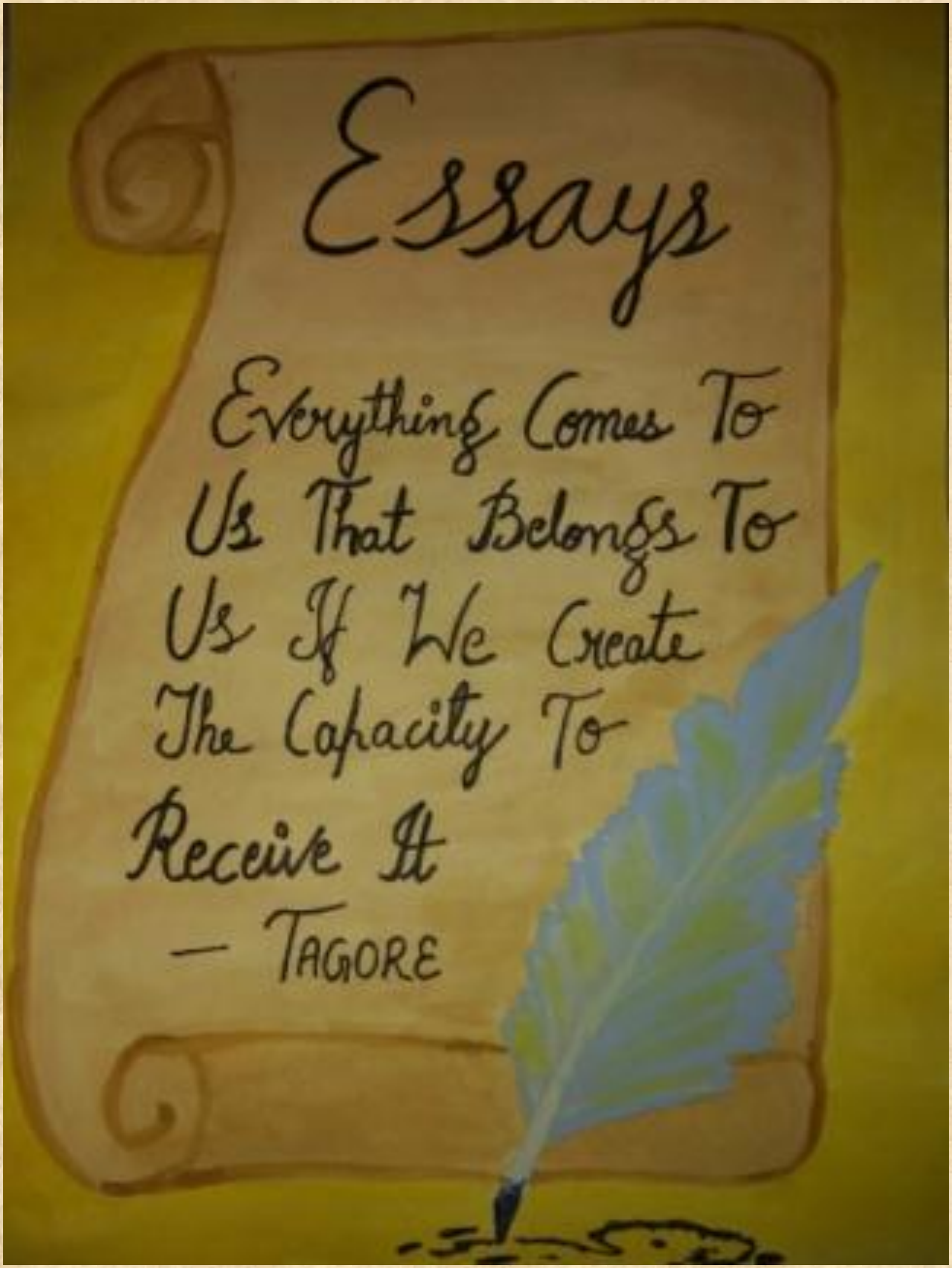
Essays
Everything Comes To Us That Belongs To Us If We Create The Capacity To Receive It
— TAGORE

भ्रष्ट्राचार का राजतन्त्र

भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है परंतु कई बार लोग इसे राजतंत्र कहने लग जाते हैं। आखिर कहे भी क्यूं नही, यह लोकतंत्र होकर भी राजतंत्र की तरह चलता है। यहां आम आदमी स्वतंत्र नही बल्कि समाज के हिसाब से चलता है। परंतु समाज से ज्यादा कोई इसे दबाता है तो वो है **भ्रष्ट्राचार**। भ्रष्ट्राचार वह कीड़ा है जो इस लोकतंत्र को खाता जा रहा है। सरकार बनती तो है लोगो के द्वारा परंतु भ्रष्ट लोगो की।

हमे बचपन से सिखाया जाता है कि चोरी और गलत काम नही करना चाहिए परंतु इन गलत कामों के बिना इस देश को सोच पाना नामुमकिन होता जा रहा है। वर्तमान काल में भ्रष्टाचार इस देश का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। शुरुआत से ही हम लोग खुद को भ्रष्टाचार का शिकार बनते देखते आए हैं। जन्म होने के बाद एम.सी.डी से अपना जन्म पत्र बनवाने के लिए हमारे पिता को रिश्वत देनी पडती है। फिर स्कूलो द्वारा भी शिक्षा को भ्रष्ट किया जाता है। यह अचंभित कर देने वाला वाक्य है परंतु सत्य है। एक जांच के दौरान यह पाया गया है कि (ट्रांस्पेरेन्सी इंटरनैशनल द्वारा यह आंकड़ें बताए गए है) 62% भारतीयों को सरकारी कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिए रिश्वत या ऊंचे दर्जे के प्रभाव का प्रयोग करना पड़ता है। साल 2008 मे पेश की गई इसी संस्था की रिपोर्ट मे बताया गया है कि भारत मे लगभग 20 करोड़ की रिश्वत अलग-अलग लोकसेवकों को (जिसमे न्यायिक सेवा के लोग भी शामिल हैं) दी जाती है।

उसी का यह परिणाम है कि भारत मे पुलिस और टैक्स एकत्र करने वाले विभागों मे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इन्ही कारणों की वजह से एक आम आदमी यह मानकर चलता है कि किसी भी सरकारी दफ्तर मे रिश्वत दिए बिना उसका कोई काम नही हो सकता। पूरी दुनिया मे भारत भ्रष्टाचार के मामले मे 14वें स्थान पर आता है।

आखिर इसे राजतंत्र न कहे तो क्या कहे, यह आम आदमी का लोकतंत्र नही बल्कि पैसे का राजतंत्र है। यह राजतंत्र अब इस देश के जड़ तक फैल चुका है, जिससे छुटकारा पाना इतना

आसान नही है, परंतु हमे इससे बचना है तो इसके लिए खुद को बदलना होगा, इस राजतन्त्र को उखाड़ फेंक, लोकतन्त्र को फिर से स्थापित करना होगा।

Shruti
I Yr Sec B

विश्वविद्यालयों में छात्र-राजनीति

भारतीय लोकतन्त्र हो या कोई भी अन्य देश का लोकतंत्र, चुनाव व राजनीति जैसी प्रक्रिया आम बात होती है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली राजनीति देश के विकास के लिये अहम मानी जाती है, और यह माना जाता है कि बडे ही सूझ-बूझ, तर्कशील और कुशल लोग ही इस राजनीति में हिस्सेदारी करते हैं। लेकिन इस बात में दो राय नही है कि वर्तमान लोकतंत्र की राजनीति बड़े ही नकारात्मक रूप से परिवर्तित हुई है, और इसका सबसे बड़ा असर यह है कि राजनीति को एक भ्रष्ट क्षेत्र माना जाने लगा है। राजनीति 'गंदी' मानी जाती है, और सामान्य जनता इससे दूर रहना चहती है। लोग किसी भी अन्य क्षेत्र का हिस्सा बने लेकिन राजनीति में कभी नही आना चहते। यह कोई छुपी हुई बात नही है कि एक खास तबके के लिये यही राजनीति कमाई और घोटाले का एक बहुत बड़ा जरिया है, वर्तमान राजनीति में राजनेता सत्ता में आने के लिये किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने को तैयार हैं।

इस प्रकार की राजनीति को देखते हुए विश्वविद्यालयों की छात्रसंघ राजनीति भी उग्र होती चली जा रही हैं। ऐसा माना जाता है कि छात्रसंघ राजनीति राष्ट्रीय राजनीति कि ओर पहली सीढी जैसी होती है। छात्रों के बीच राजनीति एक ऐसी पाठशाला जैसी है, जिसके माध्यम से छात्र छोटे स्तर पर कई मुद्दे उठाते है, खासकर वे मुद्दे जोकि छात्रों के लिये महत्वपूर्ण है. छात्रगण की समस्या सुलझाने का प्रयास करते हुए ये छात्रसंघ राष्ट्रीय स्तर पर जनता की समस्या व विकास के मुद्दे की ओर भी अग्रसर होते है और एक तरह से उसमे भी ट्रेनिंग पाते हैं।

भारत के परिपेक्ष्य में देखे तो पाते है कि आजादी के दौरान और बाद में व वर्तमान समय में छात्रसंघ राजनीति में जमीन आसमान का अंतर नजर आने लगा है। समय के साथ छात्रसंघ राजनीति एक नकारत्मक दिशा की ओर अग्रसर हो चली है। अब विश्वविद्यालयों में राजनीति एक दंगल के रूप में बदल चुकी है, जहां हर कोई राजनीति में भाग लेना चाह रहा है, चाहे वह राजनीति का 'र' भी नही जानता हो! छात्रनेता छात्रों के बीच चुनाव में, यानि की, इतने छोटे स्तर पर भी इतना पैसा खर्च करते है, और इतनी मात्रा में पैसे जुटाने के लिये भ्रष्टाचार करने से भी नही कतराते।

अब हम चुनावों के दौरान विश्वविद्यालयों और कालेजों की छात्रसंघ राजनीति की बात करते है। हमारे सामने दिल्ली युनिवर्सिटी का उदाहरण है- छात्र नेता जब अपने प्रचार करते हैं तो आसपास का माहौल अशांति में परिवर्तित हो जाता है। आमलोग जो सडक पर चलते है, उनकी गाड़ियों और यहां तक की उनकी पीठ पर अपना स्टीकर और अन्य प्रचार की चीजें चिपकाने का प्रयास करते हैं। पर्चे इत्यादि से सडकें और दीवारें भर जाती हैं। बाइकों, ट्रकों और जीपों पर रैलियां निकाल कर हुडदंग मचाते हैं, और अपने प्रचार के पैंफ्लेट्स आदि को हवा में उड़ाते हुए , शोर मचाते हुए सामान्य ट्रैफिक को अस्त-व्यस्त करते हैं। इसके अलावा छात्रों के बीच यह

शिकायत भी रहती है कि छात्र-नेता लेक्चर के दौरान चुनाव-प्रचार करने के लिये अध्यापक को पढाने से रोकते है, और २-३ मिनट का समय मांगते हुए पूरा लेक्चर प्रचार में जाया कर देते हैं। ऊपर से, इतने जोर से और शोर-गुल के साथ प्रचार करते है कि चालु कक्षाओं को परेशानी होती हैं। इस प्रकार, दिल्ली युनिवर्सिटी को ही देखे तो छात्रसंघ चुनाव के दौरान कई महीने पहले से ही पढाई का माहौल खतम कर दिया जाता है। ऐसे में, कालेज और विश्वविघालय शिक्षा के नही, बल्कि राजनीति के अखाड़े बन जाते है, जहां शिक्षा प्र कोई ध्यान नही दिया जाता।

छात्रसंघ राजनीति के दौरान, हुड़दंगई, गाली-गलौज और मार-पीट आम बात हो गई है। गर्ल्स कालेजों में बिना इजाजत घुसना, प्रचार के नाम पर हंगामा करना, और कई बार लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करना- यह सब भी आम बात हो गई है। यह सब छात्रसंघ राजनीति के दौरान अनदेखा किया जाता है। गुन्डागर्दी करने वाले और दबंग किस्म के छात्र-नेता अध्यापकों से भी बद्तमीजी करने से नही चूकते। कही गलती से ये छात्र चुनाव जीत जाये, तो इनकी खुशी देखते बनती है और जीत की खुशी मनाने के दौरान नियम-कानूनों को तोड़ना आम बात है। आतिशबाजी, पोस्टर, नगाड़े का जैसे रेला सा लग जाता है, और ऐसे मौको पर एक आम छात्र अक्सर यह सोचता होगा कि छात्रों की बीच राजनीति राष्ट्रीय राजनीति से कैसे अलग है जहां 'मनी और मसल पावर' का बोलबाला है!

चुनाव जीतने के बाद यह छात्रसंघ आम छात्रों से किये गये वादे पूरा न करके, कुछ एक कालेज फेस्टीवल, फेरवेल पार्टी, फ्रेशर आदि का आयोजन करा के यह समझते है कि उनके कर्तव्य पूरे हो गये। वे यहभूल जाते हैं कि वे सत्ता में क्युं आये हैं! छात्रों के असल मुद्दे जैसे कि क्लासरूम की व्यवस्था, मेस या कैंटीन के बढते बिल, साफ पीन का पानी, फीस का बढता दर, लाईब्रेरी की अच्छी सुविधा आदि से आजकल के छात्र-संघों का कोई लेना-देना नही होता। यानि कि, एक छोटे स्तर पर शुरूआत कर, ये छात्रनेता राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करते हैं और वहा के अनुकूल सारी 'ट्रेनिंग' पा लेते हैं! भ्रष्टाचार और खोखले विकास की राजनीति सीख लेते हैं।

मेरे अनुसार विश्वविघालयों में छात्रों की राजनीति को मार्गदर्शन की जरूरत है। उन्हें एक लोकतांत्रिक देश में राजनीति के महत्व को समझने की जरूरत है। किस प्रकार सत्ता में आने के बाद, उस सत्ता का इस्तेमाल विकास और आम जनता से जुड़े मुद्दों को हल करने में लगाना है- यह समझना उनकी जिम्मेंदारी है। किस प्रकार देश को विकास की ओर अग्रसर करना है, यह युवा वर्ग से बेहतर कोई और नही समझ सकता, और छात्र-राजनीति इस दिशा में एक शुरूआत की तरह है। छात्रों को राजनीति करनी चाहिये या नही, यह एक विवादित मुद्दा है। लेकिन मेरे अनुसार भारत जैसे देश में जहां एक बहुत बड़ा युवा-वर्ग है, वहां इतने बड़े समुदाय को राजनीति से दूर रखना ठीक नही है। जरूरत है सही दिशा में मार्गदर्शन की, और छात्रों के बीच राजनीति के माध्यम से एक समझदारी बनाने की, जोकि देश के हित में हो।

Lakshmi Maurya
III Yr Sec A

लोकतंत्र मे फैली असमानता

अगर लोकतन्त्र व्यावस्था को देखा जाये तो यह पूर्ण रूप से समानता पर बल देती है। संविधान के अनुच्छेद 14-18 समानता के अधीकारों से संबन्धित है, जिसमे यह लिखा है कि सभी भारतीय नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा व समान अवसर प्रदान किए जायगे। उनके साथ नस्ल, लिंग, जाति तथा धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जायेगा ।

अगर इन सभी बातों का विश्लेषण किया जाये तो यह पाते है कि ये बातें संविधान में तो लिखी गयी है लेकिन इसे व्यव्हार में नही लिया गया जिसके कारण समानता सही अर्थो मे लागू नही हो पाई ।

लिंग-आधारित असमानता आज पूरे देश मे फैली हुई है, महिलाओ के साथ लैन्गिक अधार पर भेदभाव किया जाता है। आज भी अधिकतर लोग इसी भेद-भाव से भरी सोच के साथ जीते है और बेटा होने पर अधिक गर्व किया जाता है। यह असमानता न केवल सोच में है बल्कि शिक्षा, अवसर, कार्यो मे भी देखी जा सकती है। भारत मे महिलाओं के लिये बहुत से कानून बने हुए है लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है, आज भी महिलाओ के साथ दूसरी श्रेणी का व्यवहार किया जाता है और उन्हें पुरुष के समान अधिकार नही दिए जाते।

यह असमानता केवल लैन्गिक असमानता तक ही सीमित नही है बल्कि यह लगभग हर सामाजिक क्षेत्र मे देखी जा सकती है.

अगर आर्थिक असमानता कि बात की जाए तो धीरे-धीरे इसमे वृद्धि होती जा रही है। इसमे कुछ लोग ऐसे है जो सामाजिक व आर्थिक नितियों का लाभ उठा रहे हैं जिसमे पूंजीपति, नेता, नौकरशाह और बिजनेसमेन आदि शामिल है। वही दुसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी है जो इन नीतियो का लाभ नही उठा पा रहे है, और गरीबी मे अपना जीवन गुजार रहे है। यह कहना गलत नही होगा कि आज अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब उसी निम्न अवस्था मे अपना जीवन गुजार रहे हैं।

इसके अतिरिक्त जातीय असमानता भी पूरे देश मे अपने पैर जमा चुकी है। आज

भी निचले स्तर की जातियों को घृणा की नजर से देखा जाता है जिसके कारण कई बार इनकी योग्यता, अकांक्षा व व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को भी नजरअंदाज किया जाता है। जातीय व्यवस्था कहने को पारंपरिक कामों पर आधारित है, लेकिन इसी अधार पर साफ-सफाई करने वाले, चमड़े का काम करने वाले लोगो को निचली जाति का बता कर हेय और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आज जातीय असमानता हमारे समाज की एक विशेषता बन गई है।

अतः यह कहना कठिन होगा कि भारतीय लोकतन्त्र में समानता पूरी तरह से लागू हो पाई है, आज भी समाज मे असमानता व्यापक रूप से फैली हुई है फिर चाहे वे लैंगिक, जातीय या आर्थिक असमानता ही क्युं न हो।

इस असमानता को दूर करने के लिये आवश्यक है कि लोगो के नजरिये में बदलाव लाया जाए, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता व क्षमता के आधार पर आंका जाना चाहिए न कि जातीय/लैंगिक और आर्थिक आधारों पर।

Zufia
III Yr Sec A

लोकतांत्रिक भारत मे बाल श्रम

भारत को आजाद हुए 69 वर्ष हो गए लेकिन क्या आज भारत पूरी तरह आजाद हुआ है? 1947 में भारत को आजादी मिली तो इसे एक लोकतांत्रिक और आधुनिक भारत कहा गया। लेकिन क्या आधुनिक भारत की आजादी को सभी लोगो के जीवन मे अमल किया गया? आज भी आधुनिक भारत मे बहुत वर्ग और समुदाय ऐसे है जिन्हें आजादी के शब्द का बोध भी नही है। हम उन सभी लोगों की बात कर रहे है जिन्हें आधुनिक भारत मे रहने के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्त नही है। आधुनिक भारत में महिलाऍ, निम्न जाति के समुदाय, अल्पसंखयक समुदाय, किन्नर समुदाय, इत्यादि जो आज भी अपने अधिकारों से वंछित है ।

इनमे से एक व्यापक समस्या है बाल श्रम की। क्या आप यह जानते है कि बाल श्रम क्या है? यह कैसे पैदा हुआ?

बाल श्रम का मतलब है कि १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों से जबरदस्ती काम करवाना। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो संविधान निर्माण के दौरान सभी समुदायों के लिये अधिकार व हितों की बात हुई और यह वादा किया गया कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जाएगा। संविधान का निर्माण तो इन बड़े वादों पर हो गया लेकिन इसे अमल में बहुत कम लोगों के लिए लाया गया।

यह कोई अनजानी बात नही है कि आजादी के समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नही थी। भारत मे कुछ ऐसे राज्य व क्षेत्र थे जंहा परिवारों को न्युनतम सुविधायें जैसे कि भोजन, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त नही थी, कुछ राज्यों की दशा ज्यादा खराब थी, जैसे कि बंगाल, बिहार, उडीसा, इत्यादि। भुखमरी और गरीबी से ग्रस्त थे इन परिवारों को बच्चों सहित अक्सर पलायन, विस्थापन और सस्ते श्रम का दंश झेलना पडता।

आज भी यही स्थिति बरकरार है, जब इन परिवारों के बच्चो को भी परिवार की मूल जरूरतों कि लिये काम करना पड़ता है। ऐसे में लडकियों के साथ ज्यादा दुर्व्यवहार और यौन-

हिंसा आम है, जैसे- घरों मे काम करते समय उनके साथ गलत व्यवहार, उन पर हाथ उठाना, कई बार उन लड़कियों को मर्दो की हवस का शिकार होना पडता हैं। लड़कियों को बेचा व खरीदा जाता था तथा उनसे गलत काम करवाए जाते है।

ऐसे बच्चो को अक्सर ऐसे स्थानों पर काम करना पडता है जैसे, ढाबें, चाय की दुकान, गाड़ी साफ करना, जूते पोलिश करना इत्यादि। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहं काम के दौरान इन बच्चो को हवा, पानी वा सूर्य के प्रकाश से वंछित होना पडता है।

बाल श्रम को रोकने के लिए तमाम सरकारी नीतियों और कानूनों के बावजूद आज भी हम अपने दैनिक जीवन में बाल श्रम को देखते है। इस समस्या की जड़ में है लोगों की गरीबी जिन्हें काम नही मिलता और रोजगार के अभाव में वे सस्ते से सस्ते में खटने को तैयार हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चों को भी मजबूरन काम करना पडता हैं। यह बात हमसे छुपी नही है कि बच्चों को खटा कर और भी मुनाफा कमाया जा सकता है, क्युंकि उन्हें वयस्कों के समान वेतन देने की जरूरत भी नही समझी जाती।

भारत ने सांतवां वेतन आयोग लाकर गरीब व अमीर के बीच के अंतर को और भी बड़ा कर दिया है। जहां एक व्यक्ति को मासिक एक लाख रूपया वेतन मिलता है वही एक गरीब व्यक्ति को 9 हजार रू. भी प्राप्त नही होते, तो इसके लिए हमारी सरकार ही जिम्मेदार है । ऐसे में बाल-श्रम जैसी समस्या कभी न खतम होने वाला रूप ले चुकी है जो कि हमारे लोकतंत्र पर बहुत बड़ा सवाल है।

Komal
II Yr Sec B

शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता

आज हम एक आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में रह रहे हैं, जो कि विश्व के सफल लोकतंत्रों में से एक है। हमारे लोकतंत्र के आधारों में से एक है कि यह पुरुषों व स्त्रियों को समान अधिकार देता है। हमारे राजनेता इस मुद्दे पर अनेकों भाषण देते हैं। यह सबसे चर्चित व विवादित विषय है। परंतु बातें किसी मसले का हल नहीं होती। एक आधुनिक सफल लोकतांत्रिक देश में रहने के बावजूद भी हमें लड़कियों के लिए लाडली योजना, सुकन्या योजना जैसी सरकारी नीतियों की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम आज भी महिला को व्यवहार व समाज दोनों में समान दर्जा नहीं दे पाए हैं? हम क्यों महिलाओं को इतना सशक्त नहीं बना पाए कि वह आत्मनिर्भर हो पाए?

भारत में पुरुषों व महिलाओं के मध्य यह असमानता सदियों से कायम है, क्योंकि भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है, जोकि दोनों लिंगों में भेद बनाए हुए है। यघपि भारतीय संविधान पुरुषों व महिलाओं को समान अधिकार देता है, परंतु व्यवहार में आज भी कायम नहीं हो पाया है। लैंगिक असमानता मनुष्य अधिकारों के विरुद्ध है। इस लैंगिक असमानता की शुरुआत परिवार में लड़के व लड़कियों के मध्य किए जाने वाले अंतर से होती है, जैसे कि शिक्षा का अवसर। माना जाता है कि शिक्षा महिलाओं के लिए नहीं बनी है न ही महिलाएँ शिक्षा के लिए बनी है।

हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार महिलाओं द्वारा भागीदारी दी गई है यह आँकड़े इस वास्तविकता को प्रस्तुत करते हैं। भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, जबकि महिला साक्षरता दर 65.46% है। इस गिरते आँकड़े का मुख्य कारण अभिभावकों की सोच है जो कि यह मानता है कि लड़कियों के लिए शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि वह विवाह से पहले पिता व विवाह उपरांत पति के अधीन रहती है। अभिभावकों के अनुसार लड़कियों पर शिक्षा में किए गए व्यय से भी कोई लाभ नहीं कमाया जा सकता। वर्तमान समाज में महिलायें केवल फिल्मों के प्रचार, विज्ञापनों में अंग प्रदर्शन द्वारा वस्तु बेचने का एकमात्र साधन बनकर रह गयी है।

भारतीय लोकतंत्र तब सशक्त होगा जब पुरुषों व महिलाओं की एक समान भागीदारी होगी। इस पितृसत्तात्मक सत्ता की सोच को बदलना होगा। वर्तमान शिक्षा क्षेत्र में महिलाएँ पुरुषों के मुकाबले अधिक प्रगतिशील हैं।

उदाहरण - 2016 की IAS परीक्षा में टीना डाबी प्रथम आई, तो दूसरी तरफ एक MBBS की छात्रा का मानवीय हद पार कर 2015 को सामूहिक बलात्कार किया गया। क्या यही देश की आधुनिकता है? ऐसे कृत्य महिलाओं को आगे बढ़ने व उनकी सामाजिक भागीदारी को रोकते हैं।

एक लोकोक्ति है- "एक स्त्री दो परिवार शिक्षित करती है।" आवश्यकता इस लोकोक्ति को साकार करने की है। परिवारों को अपनी सोच बदलनी होगी। अपने परिवार के लड़कों की भाँति अपनी लड़कियों को भी पढ़ना होगा। नवरात्रों में भारतीय समाजों में देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है, परंतु बाकी दिन उसी देवी के जीवित रूप, एक स्त्री पर अत्याचार किया जाता है।

आज अनेकों शिक्षा संस्थाओं, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाला दुर्व्यवहार, बलात्कार, शोषण की खबरें आए दिन देखने को मिलती हैं। क्यों आज का पुरुष वर्ग स्त्रियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकता? आज की परिस्थितियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि यदि सोच बदलो तो देश बदलेगा। नारी को न केवल नौ दिनों बल्कि एक व्यावहारिक सामाजिक जीवन में भी उसकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। महिलाओं को न केवल गानों, फिल्मों में धन कमाने का जरिया न समझा जाए बल्कि उन्हें भी पुरुषों की भाँति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों, शोषण, मारपीट के विरुद्ध कड़े नियम बनाए जाए।

सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ एक तरह से महिलाओं की शिक्षा क्षेत्रों में भागीदारी अग्रसर करती हैं। देश में आ रही आधुनिकता तब ही प्रदर्शित होगी जब समाज को लोगों की मानसिकता में भी आधुनिकता व सकारात्मकता आएगी। यह समय सोच बदलने का है। बेटी को बेटे की तरह प्रोत्साहित कर उसे भी आगे के लिए प्रेरित करने का है।

बेटी को पढ़ाने उसको सशक्त बनाने के लिए पूरे देश की भागीदारी की उसमें आवश्यकता है। ताकि "बेटी पढ़े और देश बढ़े।"

Ruma
II Yr Sec B

Portrayal of Women in Mass Media

Any means of communication that reaches a large audience comes under mass media, which has become a significant force in modern culture. Multimedia today forms the basis of our society. Today the way women are shown in media is different from earlier times whether it is movies or advertisements, things have worsened over the period. The portrayal of women in mass media today is to enhance the appeal of the product without regard to the interest of women in general. The media portrays women as objects and it is surprising to see them in advertisements related products like cement so that they can attract the attentions of the viewers.

More and more women are being portrayed as commodities rather than as individuals which sets a very dangerous precedent for our society. Such portrayal leads to unrealistic expectations by men about how women should look and behave. With unrealistic portrayal of women in media the audience sees them as objects of invoking vyouristic sensation. For example often degrading description is used in music videos with regard to women which creates a barrier between men and women. Men feel it is permissible in today's society damage a woman's dignity by treating them as mere commodities.

By and large female inequality has become easily permissible in the society through the constant influence of media. Gender roles are constantly reinforced through the media. Many times it is shown that man is the money maker, hard worker and a being representing 'intelligence' within the family whereas woman is baby-maker, home-maker and an 'emotional' figure in the household. This stereotyping of gender roles has a profound impact on the society. Women have always been adored and glorified for their physical attributes. We often see in TV shows and advertisements, a man choosing a skinny girl over fat girl or fair girl over a dark complexion girl, which can lead to depression among women in general about their looks which is a very unhealthy trend. Young women are especially affected by objectification in mass media. Women in general have become more obsessed with how their

body is seen by others in the society. The need to have a 'perfect body' is a result of various messages society sends in this regard directly or indirectly.

Sexual exploitation of women is very much prevalent in all the spheres of our society, be it within families, at workplaces or on the streets, which has been heightened with the sexualized projection of women in media.

These days a new trend has started of plastic or cosmetic surgery which is increasingly being promoted in our TV shows as something which can fix all the problems. People have often looked up to celebrities who themselves resort to such measures of going under the knife to acquire perfect bodies or skin. This propels the audience and more so the women, to resort to the same path to look like those they adore.

Mass media is an effective tool which creates public opinion. Television is supposed to be the mirror of the society. However, many times due to incorrect portrayal of reality some groups and communities are at the receiveing end, among which, the women are a glaring example.

Chetna
II Yr Sec B

शिक्षा का निजीकरण

लोकतांत्रिक व्यवस्था मे अधिकारों का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि संविधान मे लिखे गए ये अधिकार लोगों के विकास मे मुख्य भूमिका निभाते हैं।

इन्हीं अधिकारो में एक अधिकार है 'शिक्षा का अधिकार' जो हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है तथा इस अधिकार से ही भारत के हर 4 से 14 साल तक के बच्चें को शिक्षा का अधिकार है। तथा सरकार द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक संस्थानो मे कई सारी ओर भी सुविधाएं प्रदान की जाती है जैसे- मुफ्त शिक्षा, मीड-डे मील, छात्रो को उनकी सुविधा के लिए या आवश्यकता के लिए पैसे भी दिए जाते है। शिक्षा का अधिकार को मजबूती देने के लिए 2003 मे संविधान मे शिक्षा का अधिकार (83 वे संवैधानिक संशोधन 2000) के तहत शामिल भी किया गया। इन सब अधिकारों व सुविधा के बावजूद क्या सचमुच शिक्षा का अधिकार का लाभ सभी बच्चों तक पहुंच रहा है? यदि पहुंच रहा है तो कितने बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्राप्त हो रही है।

शायद इन सवालों से ही हम वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे। यूनिस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा 287 लाख अशिक्षित व्यस्कों की संस्था है। साल 1991 से 2006 तक अशिक्षा का स्तर 63% तक हो गया था। इस दर के ज्यादा होने का मुख्य कारण शिक्षा का निजीकरण है।

आज का युग वैश्वीकरण का है जिसके अंतर्गत हर एक जगह मे निजीकरण लाना तथा राज्य की भूमिका को सीमित करना एक मुख्य लक्ष्य है। शिक्षा जैसा बुनियादी क्षेत्र भी निजीकरण व बाजारीकरण के प्रभावों से जुड गया है। आज शिक्षा बाजार में क्रय-विक्रय करने वाली एक वस्तु बन गई है।

शिक्षा की कई संस्थाओ मे चाहे वह छोटी हो या बडी निजीकरण का प्रभाव दिखता है। निजी स्कूल चाहे वह प्राथमिक हो या उच्च स्तर के, पैसे वसूलने का मौका नही छोड़ते, कॉलेजों में भी निजीकरण की पूरी छाप दिखती है तकनीक को महत्व देने तथा आधुनिक या 'वर्ल्ड क्लास' बनाने के लिए कुछ ही समय पहले दिल्ली युनिवर्सिटी के सभी कॉलेज विद्यार्थियों की

फीस ऑनलाइन भरी गई, जोकि कई छात्रों, खासकर गरीब और तकनीकी पहुंच से महरूम छात्र तबके के अनुकूल व्यवस्था नही थी।

इस निजीकरण के दौर मे शिक्षा को पाने के लिए योग्यता मुख्य नही है बल्कि पैसा महत्व रखता है, जितना भार पैसो का होगा, डिग्री और यहां तक कि अच्छे अंक पाना विधार्थी के लिये आसान हो जाएगा। अब शिक्षा खर्चीली हो गयी है और एक तरह से विलास की वस्तु बना कर रख दी गई है जिसकी पहुंच गरीब बच्चों तक नही गई। भारत देश की विशेष परिस्थितियों में देखे, तो एक गरीब व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, जिसको वह जीवित रह सकता है, उस तक भी उसकी पहुंच बहुत मुश्किल से होती है, तो फिर इतनी महंगी शिक्षा की प्राप्ति वह कैसे कर पाएगा? शिक्षा का निजीकरण करने से शिक्षा कुछ ही सशक्त वर्गों तक सीमित रह गई है जो आर्थिक रूप से सक्षम है, अपना विकास करने में!

अंत में, शिक्षा का निजीकरण करना बिल्कुल गलत है, क्योकि इसके कारण कई सारे निम्न व आर्थिक रूप से असक्षम बच्चो के शिक्षा के अधिकार का हनन होता है जोकि लोकतांत्रिक व्यवस्था व एक देश के विकास पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। निजीकरण को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी का मापदंड नही बनाना चाहिए जो कि आज के समय में लोग कर रहे है। लोगों की यह सोच है कि निजी शिक्षा संस्थानो में ही शिक्षा अच्छी होती है। सरकारी स्कूलों में भी बच्चो को वह शिक्षा व सुविधा मिल सकती है परंतु आवश्यक है कि इन संस्थानों में सुधार लाए जाए, अध्यापकों का सही तरह से प्रशिक्षित किया जाए, विधार्थियों को सिर्फ कैरियर ही नही बल्कि समाज के प्रति जागरूक किया जाये और वे सारी सुविधाएं प्रदान करवाई जाएं जो निजी शिक्षा संस्थानों में करवाई जाती है। हर एक की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार को मुहैया कराना होगा, तभी सही अर्थो में हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार का लाभ प्राप्त हो सकता है।

Neha Chauhan
III Yr Sec A

‘पिंक’ फिल्म समीक्षा

‘पिंक’ उस पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ एक कड़ा संदेश देती है, जिससे महिलाओं और पुरुषों को समाज में अलग-अलग पैमानो पर रख कर मापा जाता हैं। यह फिल्म बताती हैं कि यदि कोई पुरुष किसी ताकतवर परिवार से होता हैं तो महिला के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल हो जाता हैं या मुश्किल बना दिया जाता हैं। यह फिल्म हमारे समाज की उस मानसिकता पर सवाल खड़े करती हैं, जो लडकियो के स्कर्ट पहनने , शराब पीने, पार्टी में जाने और रात में घर से देर तक बाहर रहने पर उनके चरित्र को गलत बताती हैं। यदि कोई लड़की अपनी घर से अलग, बाहर कहीं रहती हैं तो समाज उसे गन्दी निगाह से देखता है। लड़के या लड़की मे से गलती चाहे किसी की भी हो लेकिन पूरा समाज लड़की को ही गलत समझता हैं।

इसके साथ ही फिल्म यह भी बताती हैं कि चाहे लड़की कोई भी हो, चाहे वह कोई वैश्या हो या कोई सैक्स वर्कर हो या फिर आपकी अपनी खुद की पत्नी ही क्युं न हो- अगर वो ‘न’ कहती हैं तो किसी भी पुरुष को उसे छूने या उससे जोर-जबरदस्ती करने का कोई अधिकार नही हैं।

कहानीः- दिल्ली के पॉश इलाके में किराए पर रहने वाली तीन कामकाजी लड़कियां मीनल (तापसी), फलक (कीर्ति) और आन्द्रिया (आन्द्रिया) की कहानी हैं। तीनो लडकियां अपने घर से दूर एक किराए के मकान में रहती हैं, जिनमे से मीनल दिल्ली की, फलक लखनऊ की और आन्द्रिया मणिपुर की हैं। तीनो लडकियां एक रात रॉक कॉन्सर्ट में जाती हैं जंहा वो तीन लड़कों से मिलती हैं। रॉक कॉन्सर्ट के बाद तीनो लड़कियां उन तीनो लड़को के साथ जाती हैं जिनमे से एक का नाम राजवीर हैं, जोकि स्थानीय नेता का भतीजा है। अन्य दो युवकों की ओर से सूरजकुंड के एक रिजॉर्ट मे डिनर का निमंत्रण स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन यह रात लड़कियों के लिए मुसीबत का सबब साबित होती हैं। आन्द्रिया महसूस करती है कि डंपि (राशुल टंडन) उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा हैं और नशे मे चूर राजवीर (अंगद बेदी) मीनल के मना करने के बावजूद उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश करता हैं।

इसी बीच आत्मरक्षा के लिए मीनल राजवीर पर एक कांच की बोतल से हमला करती हैं जो उसकी आंख मे लगती हैं और उसका खून बहने लगता हैं। तीने लड़कियां इस उम्मीद के

साथ घर लौट आती हैं कि यह बात इतना आगे नही जाएगी। लेकिन तीनो लड़के, बदला लेने की दृष्टी से उन्हें बदनाम करने और डराने की कोशिश करते हैं। तीनों लड़कियों के लिए जिन्दगी आराम से जीना बहुत मुश्किल हो जाता हैं और तीनों बहुत डर जाती हैं। फलक और आन्द्रिया लडको के साथ बात करके सुलह करने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन राजवीर को अपनी करनी पर बिल्कुल भी शर्मिंदा न देख तीनो लड़कियां माफी न मांगने का फैसला करती हैं और लड़कों के खिलाफ एफ.आइ.आर लिखवाने का फैसला करती हैं। यह देख कर तीनो युवक गुस्से से बौखला जाते हैं, और मीनल को एक गाडी मे अगवा कर उसके साथ यौन हिंसा करते हैं तथा उसे धमकाते हैं। उसके बाद तीनो युवक लडकियों के खिलाफ केस दर्ज करवाते हैं। मामला कोर्ट मे पहुंचता हैं जंहा उन पर प्रॉस्टिट्यूशन का गलत आरोप लगाते हैं। वहां वकील दीपक सहगल (अमिताभ बच्चन) जो खुद मेंटल डिस्ऑर्डर का शिकार हैं, लड़कियो का केस लडते है।

फिल्म में असली ड्रामा की शुरुआत यहीं से होती हैं जोकि समाज और यहां तक की निष्पक्ष कही जाने वाली न्यायिक व्यवस्था की संकीर्ण मान्सिकता दिखाती हैं। कोर्ट मे सुनवाई के दौरान मीनल से उसके निजी संबंध, वर्जिनीटी और शराब पीने की आदत पर सवाल पूछें जाते हैं। इन सवालों के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई हैं कि समाज किस तरह से लड़के और लड़कियो को दोहरे मानकों पर रखकर आंकता हैं।

अंत मे मीनल और उसकी सहेलियों को न्याय मिलता हैं और राजवीर व उसके दोनो दोस्तो को सजा सुनाई जाती हैं।

एक छात्रा और एक लडकी होने के नाते पिंक फिल्म मुझे बहुत पसन्द आई। यह कहानी आज के संदर्भ को लेकर बहुत सही रुप से लिखी और दर्शायी गई हैं। जहां लड़कियो को पर्दे पर हमेशा की तरह सती-सावीत्री के रुप मे ना दिखाकर बिल्कुल साहसी एवम् बिंदास अंदाज में दिखाया गया हैं। लेकिन इसके बाबजूद अगर लड़की किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने मे तैयार नही है तो उस पुरुष को कोई हक नहीं हैं की वह उस लड़की को उसकी मर्जी के बिना छुए। इसके साथ ही फिल्म में आज की सच्चाई को बहुत बखूबी से दिखाया गया हैं कि चाहे जमाना कितना ही आधुनिक क्यों ना हो जाए लेकिन समाज मे लड़कियों को लड़को के मुकाबले हर मामले मे कम आंका जाता हैं।

फिल्म में लड़कियों के ‘न’ बोलने के अधिकार पर प्रकाश डाला गया हैं। ‘न’ केवल एक शब्द नही बल्कि एक शस्त्र के समान है। और इस ‘न’ का अर्थ यही है की यदि कोई स्त्री न कहती है तो इसका मतलब है कि किसी भी पुरुष को उसे छूने का, या फिर किसी भी और तरीके से उसपर अपना अधिकार जमाने का, जोर-जबरदस्ती करने का कोई हक नही है। पुरुष को इस ‘न’ का सम्मान करना चाहिए, तभी कोई भी महिला सही मायने में, आजादी के साथ एक स्वतंत्र जीवन जीने में सफल होगी।

Shaheen
III Yr Sec A

लोकतंत्र व न्यायपालिका

भारत में लोकतांत्रिक शासन को मुख्यतः तीन अंगों द्वारा संचालित किया जाता है- कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका- ये तीनो अंग संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शासन को चलाते हैं।

अब हम लोकतंत्र व न्यायपालिका के संबंध पर गौर करेंगे। लोकतंत्र के बुनियादी आधारों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय प्रमुख हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस देश मे सभी समान हों, स्वतंत्रता हो, सबको समान रुप से न्याय मिले वहां लोकतंत्र सफल हैं। भारत मे संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को एक नागरिक के आधार पर मौलिक अधिकार प्रदान करके समानता के सिद्धांत को तो स्पष्ट किया गया हैं। परन्तु क्या भारत में न्याय भी सबको समान रुप से मिलता हैं? क्या न्यायपालिका बिना भेदभाव के सभी को न्याय प्रदान करती हैं? समानता कायम करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही हैं, इस पर गौर करना जरूरी है।

न्यायपालिका की भूमिका को लेकर दो मत दिए जा सकते हैं। पहला, न्यायपालिका के न्यायिक पुनर्निरीक्षण व न्यायिक सक्रियतावाद का साधन जनहित याचिका हैं जिसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति स्वयं न्याय पाने मे असमर्थ हो, तो उसके लिये अन्य कोई भी जनहित याचिका दायर कर सकता हैं। वहीं न्यायिक पुनर्निरीक्षण में न्यायालय द्वारा किसी भी फैसले की संवैधानिक जांच की जा सकती हैं। इसका उदाहरण- 'याकूब मेनन केस' (2015) है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही फैसले पर पुनः विचार विमर्श किया। इस केस पर पुनः विचार के लिए पहली बार सर्वोच्च न्यायालय रात भर जागी थी, यह एक ऐतिहासिक घटना थी।

दूसरा उदाहरण है 'निर्भया केस' (2012) जिसमें पीडिता लडकी के साथ बलात्कार करने वाले सभी गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दी गई। ये केस न्यायपालिका की सकारात्मक भूमिका व शीघ्र अति शीघ्र न्याय प्रदान करने की झलक दिखलाता हैं।

न्यायपालिका की भूमिका को लेकर दूसरे मत पर यदि विचार किया जाए तो इसमें न्यायपालिका की व न्याय की स्थिति बेहतर नही हैं। प्रत्येक व्यक्ति न्याय की आशा तो करता हैं परन्तु कई बार उसे न्याय मिलने मे इतना विलम्ब होता हैं कि वह न्याय पाने की आशा ही खो देता हैं। कितने मुकद्दमें आज हमारे कोर्टों में रुके पड़े हैं, या चल रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि आज

न्याय पाना बहुत महंगा हो गया हैं क्युंकि न्यायिक खर्चे, वकीलो की फीस इतनी ज्यादा हैं कि गरीब व्यक्ति के लिए तो यह पहुंच के बाहर है।

ये भी कहा जाता है कि न्याय प्रदान करने मे भी भेदभाव किया जाता है। कितने ही नेता, अभिनेता, बड़े-बड़े अधिकारी हैं जिन्हें कभी कोई सजा नही होती जैसे- 'चारा घोटाला केस' जिसमें लालू प्रसाद यादव को सजा होने के बाद भी वो जेल से बाहर है; 'हिट एण्ड रन केस' जो 12 साल तक चला और अंत में कथित दोषी 'सलमान खान' (अभिनेता) को बरी कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर कितने ही निर्दोष व्यक्तियों को इन बडी-बडी हस्तियों द्वारा गलत आरोपों में फंसा दिया जाता है और वे बिना अपराध के जेलों में सजा काटते हैं।

अतः मेरे विचारानुसार जहां न्यायिक सक्रियतावाद व न्यायिक पुनर्निरीक्षण द्वारा न्याय को अधिक सक्रिय व पारदर्शिता प्रदान की जा रही हैं, वही ऐसा भी है कि न्याय अभी स्वयं न्याय के लिए तरस रहा है। न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी के कारण कितने मुकद्दमे ऐसे है जिनका फैसला कई-कई सालों से नही हुआ हैं। अतः आवश्यक है कि न्यायिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव किए जाएं ताकि न्याय को जन-जन तक पहुंचाया जा सके।

Pooja
III Yr Sec A

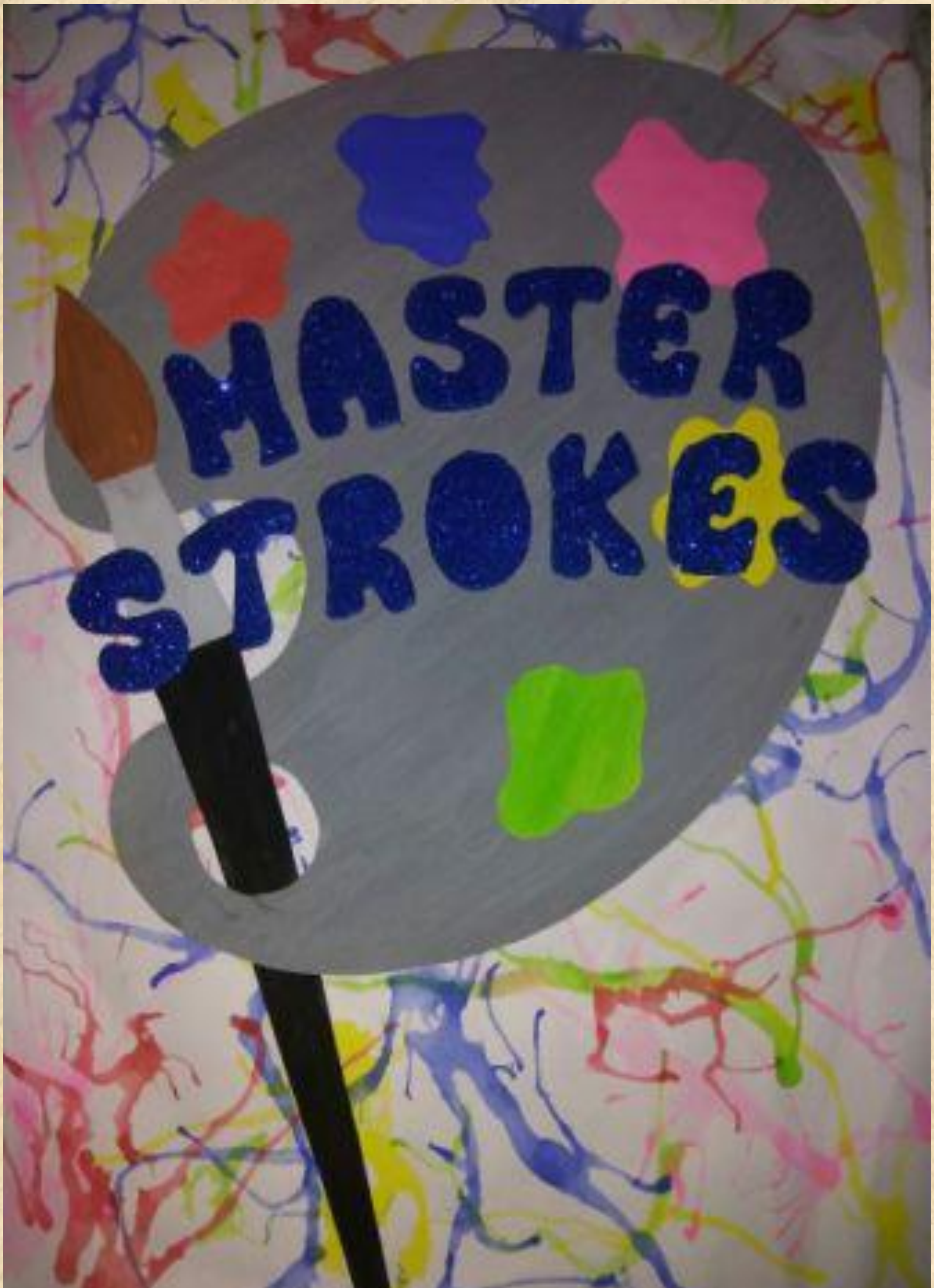
MASTER STROKES

Democracy Impersonified as Unity and Strength!

-Rajshree

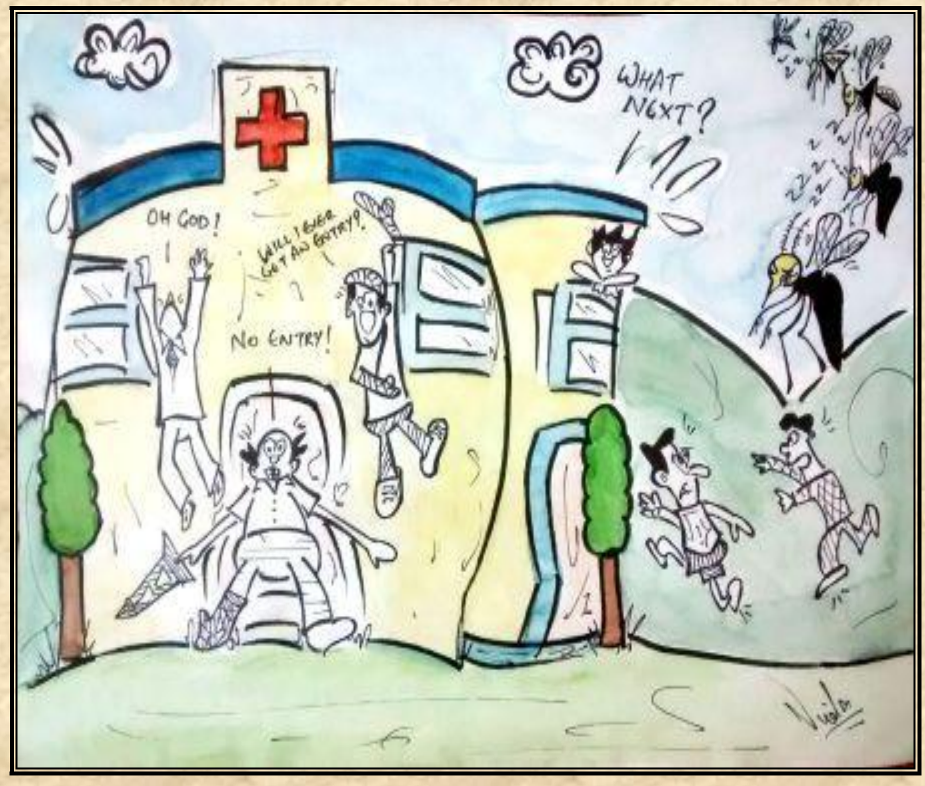

When Mosquitoes Begin to Give Nightmares!
Wither Swacchha Bharat Abhiyan?

-Nida

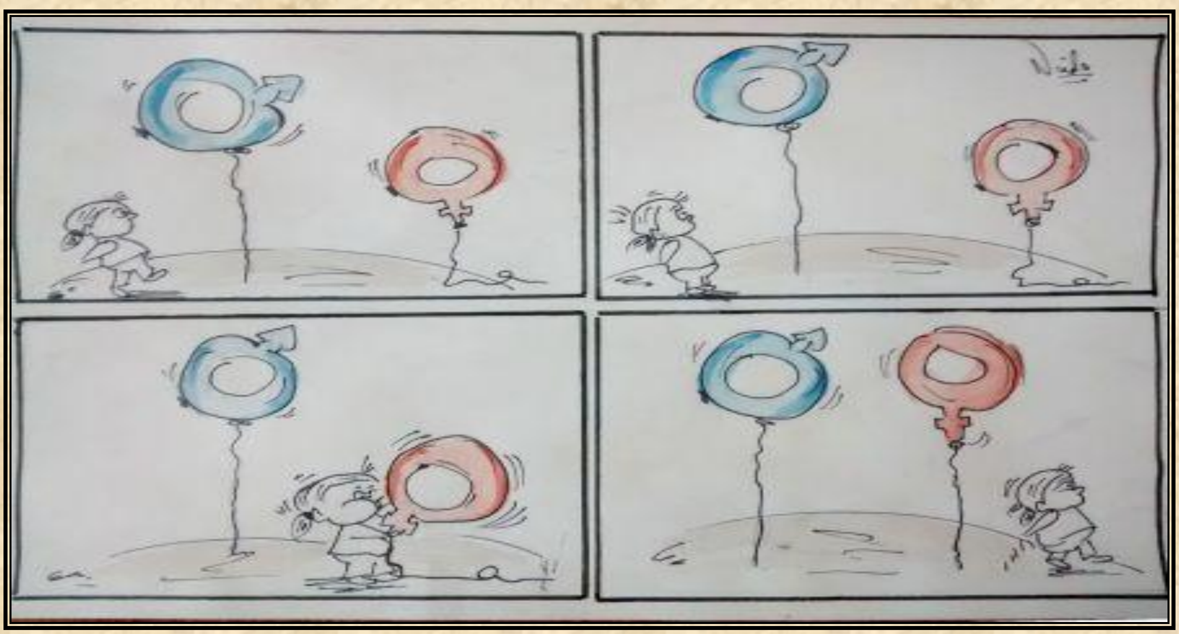

Towards Building a Gender-just Society!

-Nida

A Take on Gender Inequality at Workplaces

-Nida

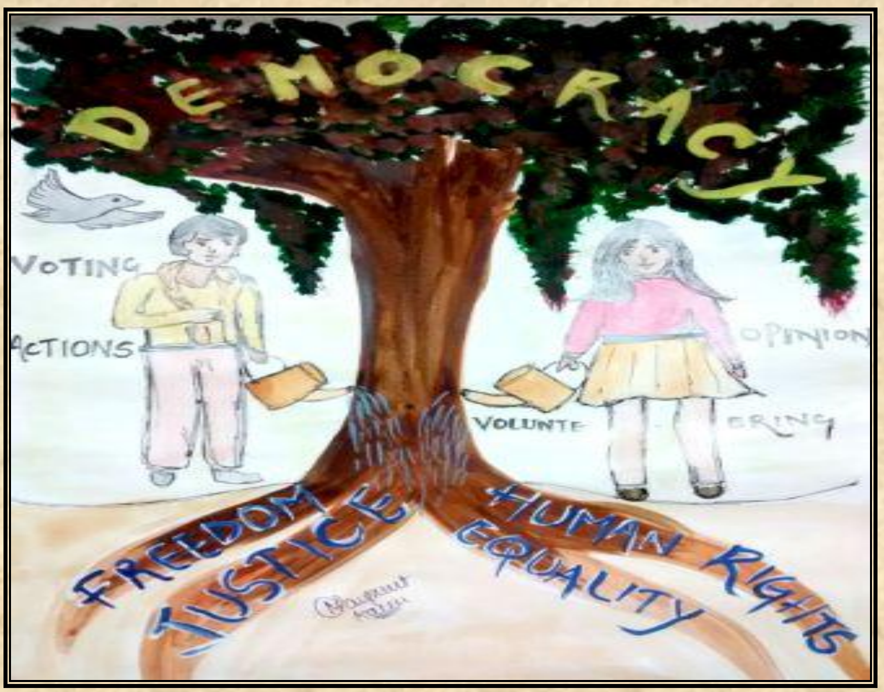

Roots of Democracy

-Manpreet

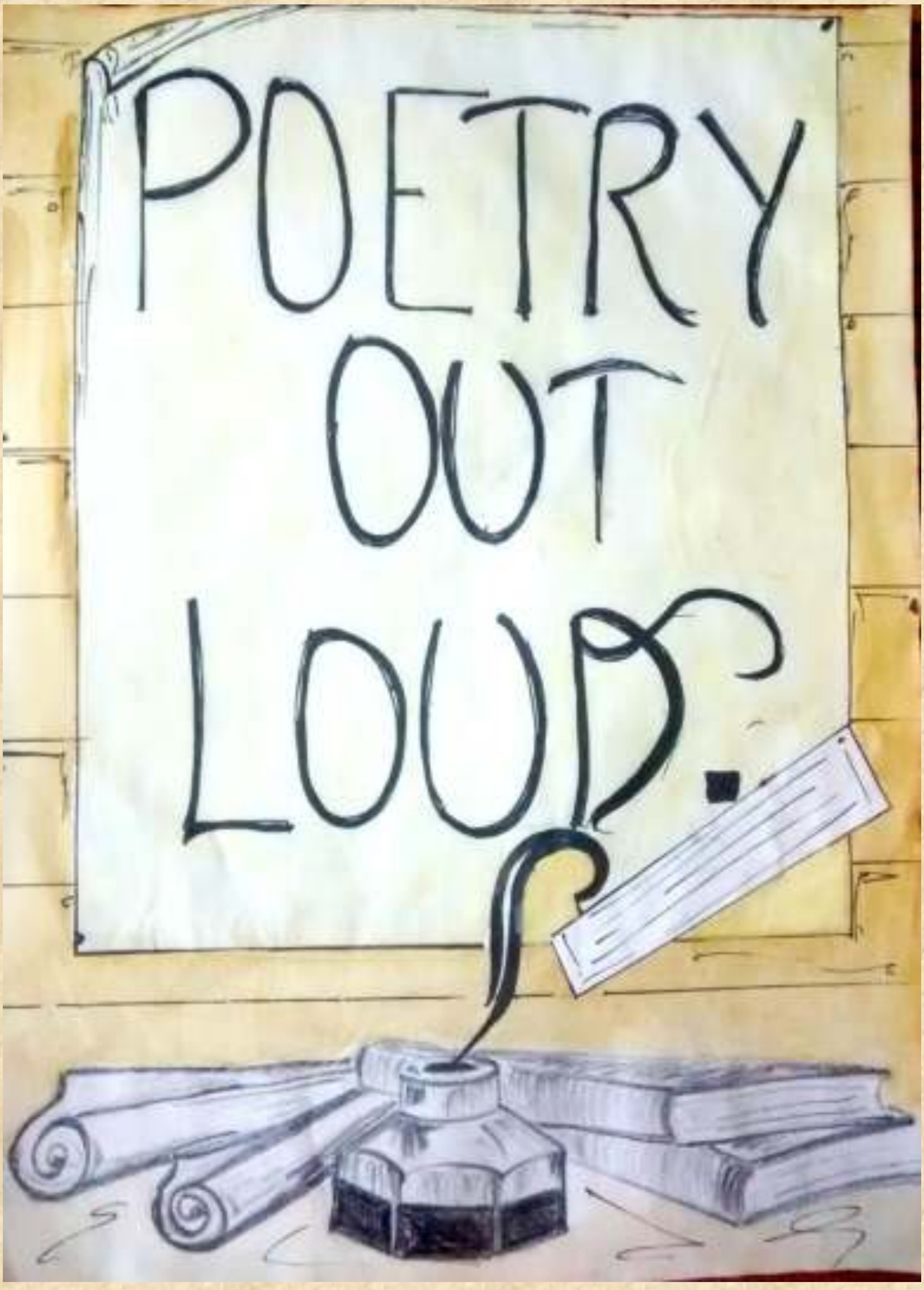
POETRY
OUT
LOUD.

आज का अखबार

आज का अखबार जो है मेरे सामने, बहुत से पेज हैं उसमें,
अलग-अलग विवादों के,जिन पर हो रही हैं देश में बातें,
कहीं किसी के साथ भेदभाव,कहीं किसी पर हो रहे हैं अत्याचार
कहीं छपी है किसी भ्रष्ट कर्मचारी की न्यूज, और बस यही सब कुछ दिखता है रोज सुबह हर बार।

बहुत से सवाल उमड़ते हैं मेरे मन में,
वैसे ही जैसे शायद उमड़ते होंगे आपके भी तन में।
सीधा सवाल तब जाता है लोकतंत्र पर, उच्च शिक्षा, राम राज और विकास के मंत्र पर,
देखते हैं हम रोज अखबार, करते हैं कितना विचार।
जूझते हैं उन सवालों से बार-बार, पर समझ नहीं आता क्या दर्शाना चाहता है हमें, यह आज का अखबार।

उजागर करता है जो देश की सच्चाई।
दिखती है जहाँ लोकतंत्र की अच्छाई।
लोकतंत्र अपनाया हमने हो गए हैं कई साल,
फिर भी समझ नहीं आता, कैसे है कुछ लोगों के हाथ में देश का सारा माल।

सिमट कर रह गई है आज हमारी आजादी,
देखकर लगता है देश की कहीं हो न जाए बर्बादी।
बोलने को हमारे पास हैं सारे अधिकार,
फिर भी हम क्यों सहते हैं अफसरों का निर्मम व्यवहार।
जानते तो शायद हम सब हैं, अपने सारे मौलिक अधिकार,
फिर भी क्यों नहीं होता है,जात-पात का बहिष्कार।
सरकारी अस्पतालों की भी एक खबर है यहाँ,
कैसा देश है मेरा, लोग मर जाते हैं बिना इलाज के जहाँ।

देखकर ये सब सोच में पड़ जाता है मेरा मन, तब क्या हो जाता है इन हुकमरानों को जब होते हैं चुनाव,
बड़े-बड़े वादे और झूठे सपने दिखाते हैं,
जब ये घर-घर, हाथ जोड़कर वोट माँगने आते हैं।
आ जाता है रिज़ल्ट और खत्म हो जाती है चुनाव प्रक्रिया,
बारी तो हमारी है,अब देखने की इनकी अभीक्रिया।
जीत जाती है वह पार्टी, जिसके झांसे होते हैं बड़े,
वादे झूठे होते हैं इनके, फिर भी क्यों हम सुनते हैं होकर इन्हें खड़े।

यहाँ लगते हैं विकास के नारे, जहाँ बेरोजगारी है पैर पसारे,
अच्छी शिक्षा तो बस बोलने की बात है।
सरकारी स्कूल का बच्चा फिर क्यों खाता मात है।
क्या करना इस अखबार का, क्या करना इस दु:ख भरे देश के व्यवहार का।
जितने भी दिन बदलें, या बदलें हम अखबार,
नहीं बदल सकतीं ये खबरें,जो छपती हैं रोज लेकर नए अवतार,
जब देखो तब कुछ उत्साहजनक नहीं मिलता है,
बस ताने कस कर, हर नेता विरोधी पार्टी पर हंसता है।
लोकतंत्र की पीठ पीछे, कौन-कैसे ढोंग ये रचता है।
लोकतंत्र की बातों की भूलभुलैया में, हमेशा आम आदमी ही फंसता है।

Jyoti Mishra
IIIrd Yr Sec A

नेताओं के विचार

देखो देखो, दुनिया के विचार देखो,
आज ये, कल वो
भारत का राजनीतिक आचार देखो!

बडे-बडे वादे हैं,
कुर्सी के बाद अब आधे हैं!
फिर बन गयीं
जनता लाचार देखो
देखो देखो, भारत का राजनीतिक आचार देखो!

कुर्सी है ऐसी जो सबका दिल लुभाती है,
कुर्सी मिलते ही
जनता फिर बन गयीं लाचार देखों!
देखो देखो, भारत का राजनीतिक आचार देखो!

एक से बढकर एक आते है,
फिर ठेंगा दिखा कर सब चले जाते है!
कुछ ऐसे मुद्दे हैंजो सालो-साल बन्द बताते हैं,
लेकिन चुनाव के समय सब याद आ जाते है!
देखो देखो, भारत का राजनीतिक आचार देखो!

हिन्दू को राम के नाम से
मुस्लिम को खुदा के नाम से लड़वाना है,
और इसी बहाने अपना काम निकलवाना है!
देखो देखो, भारत का राजनीतिक आचार देखो!

कहते है एकता में विकास है पर,
देश के आधे पैसे तो नेताओ के पास है!
नेताओं का बोलबाला है,
इनकी तू-तू मैं-मैं में
जनता हो गयी लाचार देखों!
देखो देखो, भारत का राजनीतिक आचार देखो!

विदेशी कम्पनियां खूब लाभ कमाती हैं,
देशवासियों की मजबूरी बन जाती हैं!
पर, भारत की आधी कंपनियां डूब के रह जाती हैं!
देखो देखो, भारत का राजनीतिक आचार देखो!

भारत की असीम सुन्दरता दिखाते हैं,
पर, भारत का कचड़ा साफ नही करवाते हैं!
किसको हुई हानि, और किसको हुअ लाभ देखो,
देखो देखो, भारत का राजनीतिक आचार देखो!

Jyoti Tiwari
I Yr Sec B

UNDOING BELIEFS

Let alone the shrines of redtapism prosper,

I am an atheist; beliefs are a complete wonder,

Let alone the temples worship the system,

I am against these reservations,

Let alone the climate of hierarchy change,

I am the equal man; second citizenship is a hoax,

Let alone the world be globalized,

I am an outdated version firmly against indirect technological hegemony,

Let alone the world be pleased with machines,

I will find myself a child of humane aspirations...

Drishti
III Yr Sec A

देश का हाल!

उंचे तिरंगे को सलामी हमने दे दी हैं
शान से कहते हैं हम सब, हम जैसा न कोई है!
सच की कहते है हम, हम जैसा न कोई है
गंगा है मैली, सरस्वती है लुप्त, और जमुना जहरीली है!

धर्म के नाम पर बंटीं हैं जनता सारी, सारा घपला सरकारी है!
धर्म के नाम पर लड़वाना, नेताओं की समझदारी है!

कुर्सी से है सबको प्यार, खड़ा न रह पाता है कोई,
कोई खड़ा है कमल लेकर, किसी ने खुद के हाथ ही खड़ेकिये!
आखिर घड़ी, हाथी और लालटेन ने भी,
काम बहुत बड़े किये!
अब तो मफलर वाले बाबू पीछे पड़े है सबके लेकर हाथ में झाड़ु,
कश्मीर के नाम पर लड़ते हर साल,
यह भी तो है पंडितजी का ही कमाल!

गौमाता से है सबको प्यार, औरतों का न है सम्मान!
गौमाता है सबकी प्यारी, पर चारों तरफ है देह के व्यापारी!
अंत में यही कहना चाहती हूं
इन दिवंगडों के महान् भारत को कुछ सुधारना चाहती हूं!

Shruti
I Yr Sec B

लोकतंत्र की आड़ में

लोकतंत्र की आड़ में होते सारे काम,
चाहे चोरी, चाहे डकैती, चाहे काम तमाम
लोकतंत्र या जनतंत्र, हो चाहे गणतंत्र,
नाम चाहे जो भी हो पर है तो ये परतंत्र

नेताओं की बस एक ही इच्छा,
बस उनका ही परचम लहराए
चाहे ऐसे, चाहे वैसे,
कोई भी तरीका जो उनको भाए
चुनावों में हाथ जोड़ माँगे वे वोट,
फिर चाहे जनता भाड़ में जाए
लोकतंत्र की आड़ में

राष्ट्र को मिली थी एक संसद,
देश के कानून बनाने को
पर होता वहाँ तगड़ा घमासान,
खुद को सर्वोच्च दिखाने को

क्या जूते और क्या चप्पल,
फेंके जाते चारों ओर
ऐसे लड़ते, ऐसे भिड़ते,
जनप्रतिनिधि नहीं, हों वे सारे ढोर
लोकतंत्र की आड़ में

भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट हैं दल,
भ्रष्ट है सारी सरकार
बोफोर्स, कामनवेल्थ, सत्यम,
चारा-चूज़ा, कोलगेट व ताज,
इसमें हुआ जनता का पैसा खाक
टैक्स भरते कमर टूट गई,

जनता करती हाहाकार
लोकतंत्र की आड़ में

जात-पाँत पर बँटते वोट,
ऊँच-नीच का बड़ा खोट
आरक्षण है इक नया मुद्दा,
होता अब जिसपर दंगा
हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख-ईसाई,
सब करते इक दूजे की खिंचाई

धर्म-कर्म है बड़ा हथकण्डा,
होता इस पर ढोंग-प्रपंच
जब परदा हो सरकारी रूप,
तब होता दंगा और लोग जाते सब भूल

लोकतंत्र की आड़ में
औरत की तो वही कहानी,
आँचल में दूध और आँखों में पानी
न समानता, न उसको आजादी,
हर जगत उसकी बर्बादी

देश को दिया माता का रूप,
पर बेइज्ज़त कर उसे किया कुरूप
कबसे खड़ी संसद के द्वार,
प्रवेश तो खैर दिया नहीं,
आँचल छीन दिया दुत्कार
लोकतंत्र की आड़ में

जो देखा इन सत्तर सालों में,
जनता नहीं भूलेगी ये सब
दिन वह अब दूर नहीं,
कि-उठ खड़ी होगी वह जब

आंदोलन से अनशन तक,
करेगी हर प्रयास वो मरते दम तक
गाँधी, भगत, सुभाष और अन्ना,
फिर होगा सबका हाथ थामना
राम-राज फिर आएगा,
सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा!

Radha
III Yr Sec A

INDIAN DEMOCRACY: A CRITICAL ANALYSIS

One billion people,
Selecting, a few
To serve us as they say
To rule as they do.

A prolifically diversified nation
Being one sixth of world's population
Still stands with democracy, in complete locomotion.

A well defined democracy
With a plethora of religion,
A uniform electoral system.

Many described it as foolhardy,
Saying that it would become
An ordeal with impending jeopardy

With it, commenced our political
And ideological goals,
Democracy unfurling itself in various optimistic modes

Enormous classes of linguistic diversity
Formed a fine Constituent Assembly

From separation of power
To Universal Indian Citizenship
Were made justifiable,
Through constitutional right,
Powerful and esoteric leadership

Scandals of kickbacks, ideas of corruption
Topped by subtle ignominious exploitation
Economies of influence today
Delivers brusque manipulation

State and district conflicts, leading to high insurgencies,
Democracy now is questioned for its real-politik credibilities

But whatever it may be for normal citizens,
Vote is a strong weapon representing
Democratic v/s despotic confrontation

Friends this is the irony of democracy
That indelible black ink,
Can take back your so called
Power, position and paisa!!!

This is why we call it democracy

Akanksha
I Yr Sec A

ONE WORLD

A world order so unique,
Identities beyond orthodox surnames,
A community so global,
United thoughts,
A global custom of dominance and authoritarianism,
A reach so deep in roots,
Surfacing cooperation, our globe,
Regions sacrificed for national good,
Nations manipulated for international good,
Ethnicity being in question,
Modernization or polarization?
Gender equality but regional ragging,
Social movements but political rigidity,
United we win, divided we fall,
Still the division so immaculate,
Piercing the hearts of humanness,
Calling it one world,
One globe,
One religion,
One system,
One addiction- money, power, fame and guiltless scope for more...

Drishti
III Yr Sec A

Interviewing the Young Democrats

Q1. What is your opinion on Indian democracy?

Zufia: Idealism exceeds practicality. No doubt we have amazing ideas but execution lacks big time.

Q2. Democracy is all about rule for the people, by the people. Do you feel India is ruled by the masses & not the classes?

Neha: I believe everything depends on acceptability. The elite class believes it is the benefiter whereas the working class accepts its benefits and losses. There is a need for the elite to come down to the level of the masses to be treated equally. India today is ruled by elite and not the masses.

Q3. Which is the one sector, you feel requires improvement?

Megha: Education is still a lacking field. If not looked at & taken care of immediately, this would lead to the absolute failure of democracy.

Q4. One incident when Indians actually demonstrated the power of unity for change recently?

Shaheen: Many people's movements have influenced decision making in India throughout time & places, if one has to name a recent such event then it has to be the famous Nirbhaya case. I believe in democracy and the power of vote & so should everyone.

Q5. Reservation is one subject which gets incorporated in democracy related controversies. Do you think the kind of reservation system India has, will actually help its socio-economic situation?

Pooja: The current socio-economic situation requires a well planned 'need-based' reservation. Gone are the days when ten years of reservation was helping the needy. Now it has become an exploitation of the government facilities.

Q6. Democracy derives its meaning from many different angles & perspectives. What is the one issue you feel that it fails to address through its meaning?

Laxmi: Student migration. I am a student & when I got into DU, my whole family had to shift here as the state universities don't have that much importance when compared to DU. My only question therefore is, when will education be equally good everywhere?

Q7. Don't you think we are responsible for such blind eyes executions?

Ekta: I believe we are to be blamed. Yes, we cause confusion when we don't understand the 'what' & 'how' of something. In my opinion, until & unless people start understanding what politics actually is, execution shall remain a problem in this country.

Q8. Democracy is nothing but voicing the mass opinion. Do you think right to expression is being misused in the modern time period?

Neha: I agree with on the first statement. Our democracy needs improvements from time to time. What better way than right to expression? I do feel that some people misuse this beautiful feature of our democracy, but more or less freedom to express causes positive change only.

Q9. What is the most important question in democracy according to you?

Ekta: The most basic question is in itself the most important question regarding democracy & that is-whom to vote & why should one vote at all? We don't vote on behalf of China, England or Pakistan. We vote for us & the betterment of our country. This should be kept in mind as we aren't any third party, the decision we take directly affects us.

Q10. Let's have your opinions on education & democracy.

Shikha: Minority communities should be acknowledged. There still are people who can not afford education & thus are forced to suffer in poverty.

Harshita: There are gender differences prevailing in our country. Girls still have difficulty in getting education as compared to boys.

Namrata: Education has become a 'brand'. Everything seems to come down to showing off. The majority has made education a business.

Zufia: Democracy flourishes when there's apt execution & acceptance of social responsibility. It is our responsibility to ensure social justice & not alone the role of the State.

Pooja: Understanding politics is one thing. But we have to ensure that politics doesn't come in the way of successful functioning of the democracy. We still need to establish equilibrium.

Neetu: We have to come out of our cocoons & fight against corruption. Its high time. We, by not addressing this issue, are only complicating the situation.

Jyoti: There's bias in private & public education. The government should ensure we get equal education & importance be provided to all institutions & norms be followed.

Ekta: I would conclude in mere three words-reservation ignores potential.

Drishti
III Yr Sec A

The Semester Gone By

The Political Science Meet, 5 September, 2016

As a novel way of welcoming the fresh batch of students in the department, the political science teachers and students' community at Mata Sundri organized a glittering meet on September 5, 2016. Built around the theme of Indian democracy, the political science meet included a number of events and programs combining the twin elements of education and fun. Through a wide range of activities, the political science meet was successful in initiating the new batch of students into the life at political science department, giving them umpteen glimpses of what lay ahead in the coming years. Through exciting programs based on the theme of democracy, like plays and quiz, the meet deftly proved to the students, both older batches and the new, that academics can be both enlightening and enjoyable at the same time. The meet provided a warm platform for the new batch to get to know and interact with their fellow students and teachers in the department. It was heartwarming to see that the meet was attended by a huge turnout of students and teachers alike, both as participants and the larger audience.

The meet opened with a welcome note by the current Teacher-in-charge, Dr. Madhuri Sukhija who spoke encouraging words for the students by way of introducing them to the department. She also put across the crucial theme of the meet, the dynamics of Indian democracy- a question that is ever so important for budding citizens like the students, with important responsibilities towards the country and society. This was followed by a range of performances by students showcasing talent and glitz. First was an enchanting **dance performance** built around the **theme of**

women empowerment. Performed by a group of three students, the performance mapped the essential journey of a woman through different walks of life, narrating the story of discrimination and struggle for equality.

Exploring different mediums of expressing the theme of the day, the political science meet presented two **plays** before the audience- the first one called **Shiksha ka Circus**, which talked about the ills of privatization and neoliberal restructuring that plague the education system in contemporary times; the second one being, **Bhrasht Tantra, Trast Samaj** based on one of the most pervasive problems facing the political system as well as society at large, namely, corruption. Instantly striking a chord with the audience, the plays not only highlighted some of the very grave challenges before our democracy, but also proved the oft-quoted power of theatre to connect to a wide audience.

The plays were interjected by poetry recitation, especially mentionable among which is **Desh pe Tanch**, a poem penned and recited by a student, followed by a solo act of **mimicry** on the life of politicians and a **polytoon** on **Swacchha Bharat Abhiyan**- all related to the larger theme of democracy in India, exploring its various facets in varied ways.

One of the highlights of the political science meet was the **Quiz competition** between the newest students to join the department, that is, the first year batch, as a way of testing their knowledge related to the political system in the country. By means of audio clips, the participants were asked to first identify the speaker, and then answer four related questions. More than merely testing the extent of

knowledge, this particular segment of the meet was intended to educate and equip the students the know-how about the important leaders who contributed in shaping the democratic structure in the country since its independence. It was promising to see that several participants were able to not only correctly identify the historical figure featuring in the audio clip, but also were able to answer all the related questions, displaying adequate acquaintance with the historical-political structure of the country.

The political science meet concluded with a power packed **folk dance** segment, displaying the quintessential diversity that holds our democracy together. This segment included folk dances from diverse and rich cultures of Rajasthan, Kashmir, Gujarat and Punjab, only to culminate by bringing them together as colorful beads strewn together through one string. Through music and dance, this segment celebrated the much applauded theme of unity in diversity that is a hallmark of the democratic structure in the country.

Over all, the political science meet was successful in putting forth a platform for an enjoyable and educative afternoon of interaction, theatre, music and dance, as well as brainstorming. With an ambience of warmth and welcome, the political science meet set rolling the onward process of the current semester with all its activities.

Invited Talk, Department of Political Science, 21 September, 2016

One of the glittering highlights of the current semester was the talk organized by the Department of Political Science, Mata Sundri College on September 21. The topics for discussion included two themes, first, 'Emerging Trends and Issues in International Relations' and second, 'Why Legal Literacy?'The distinguished speakers invited for the talk were Prof. Navneeta Chaddha, Head-of-Department, Delhi University and Prof. Ujjwal Singh, Reader and former HoD, Delhi University. Though seemingly unrelated topics, it was intended that the students be given an opportunity to debate and discuss the latest developments within various sub-disciplines of political science, both old and new. While international relations is a dynamic paper that the students of political science are not unfamiliar with, taught as it is, at various stages at undergraduate and postgraduate levels, a paper on legal literacy, designated as 'Your Laws, Your Rights'-which was the central theme of the lecture by Prof. Ujjwal Singh- has recently been introduced as a skill-based paper as part of the new CBCS curriculum. It was expected that a lecture on the imperativeness of legal literacy in contemporary times would underline the importance of a course like this at the undergraduate level, bringing the students a step closer to understanding the wide spectrum of laws of the country. On the other hand, an in-depth discussion of the evolving discipline of international relations in contemporary times was expected to throw crucial light on the fast changing reality of the world before our eyes, which necessitates developing new disciplinary and methodological tools to grasp it.

Given the fact that it is not very often that students get a chance to hear live, the eminent scholars they read in class, it was no surprise that the talk attracted huge participation from the students of the department of political science, as well as other departments, and a good number of teachers. After a welcome note by Dr Madhuri Sukhija, TIC, Political Science Department, the speakers took charge and delivered impactful and thought-provoking lectures on their respective topics. Prof. Navneeta, speaking on the changing dynamics of the discipline of international relations (IR), highlighted the crucial issue of how the discipline of IR is fast-transforming in order to understand and respond to the changing global reality. Describing it as a 'sea-churning', she poignantly pointed out the sets of 'negatives' as well as 'positives' attached to such a process. Irrespective of the pros and cons, she called it an 'exciting' phase for the discipline as it tries to fill the 'past silences' within itself, as well as, moves forward to expand its disciplinary boundaries to become more inclusive and critical. In this process, the new emergent discipline of IR helps us to question the 'obvious' and the 'givens' within the discipline, replacing it with new knowledge systems and methodological tools to understand the world around us.

The next speaker, Prof. Ujjwal Singh, speaking on the importance of the process of legal literacy for the citizens, raised some pertinent challenges in the process of ensuring justice through what is termed as the rule of law. Calling it a 'difficult' process which is bereft with challenges, the speaker drew a parallel with a 'double-edged' sword, implying that the processes of law empower, as well as *dis*-empower; they strengthen and expand citizenship, at the same time, curtailing its boundaries through the processes of codification and enlistment. Prof. Singh highlighted that a sub-disciplinary course on legal literacy, helps to understand both these 'faces' of the legal structure in the country. In addition, he underlined the crucial

fact that the legal processes cannot be abstracted from the social whole, implying that the legal structure impacts and is impacted upon by the larger societal forces.

The lectures were followed by a round of questions from the students and teachers, and it only helped to take forward the discussion in important and new directions.

Inter-College Debate Competition, 7 November, 2016

The Department of Political Science organized an "Inter-Departmental Debate on the topic "Freedom of Speech is the true test of Democracy" on 7th of November, 2016. Freedom of speech is regarded as the first condition of liberty. In fact, freedom of speech and expression is the greatest given opportunity for a democracy. The essence of free speech is the ability to think and speak freely and obtain information from others through publications and public discourse without fear of retribution, restriction or repression by the government or others. There were fourteen participants from various departments of the college. It was a thought provoking debate where the students put forth their arguments for and against the motion.

Some argued that in modern times, it is widely accepted that the right to freedom of speech is the essence of free society and it must safeguarded at all time. The quantum of this basic freedom granted to the citizens becomes the standard to determine the quality of democracy in a country. The participants spoke vehemently on the issue and came up with their perspective regarding the same.

However,some considered right to speech as one of the many conditions of true democracy and not the only one like protection of rights of citizens, free and fair elections, wider opportunities for meaningful participation in civic affairs for citizens and a limited and constitutional government along with rule of law are the other pre-conditions of democracy. While others consider widespread socio-economic equality as another test of a true democracy in absence of which democracy becomes hollow.

The students who were an audience to the show were actively involved with interjections to the participants. It was a healthy debate and the audience thoroughly enjoyed. With healthy and intelligible deliberation on the topic, the activity proved to be an enlightened and illuminating endeavor.

Reminiscences

Celebrating Teachers Day at Political Science Meet, 5 Sep, 2016

Different Hues of the Political Science Meet, Sep 5 2016

Glimpses of the Play 'Shiksha ka Circus' , Political Science Meet, Sep 5 2015

Beloved Teachers as Audience and Judges, the Political Science Meet 5 Sep 2016

Rapt in Thought, the Political Science Dept. Talk 21 Sep, 2016

Our Contributors

The Editorial Team

CALL FOR SUBMISSIONS

We invite submissions for the next edition of the VOICE.

The length of the articles should be a minimum of 500 words and should not exceed 1000 words.

You can e-mail your submissions at the following:
voicemsc2016@gmail.com

For direct submission and any other queries, please contact,

Dr. Madhuri Sukhija
TIC & Faculty Editor,
Dept. of Political Science

Drishti Bannerjee
Student Editor,
Political Science Department